दुर्लभ धातुओं पर चीन का एकाधिकार

दुर्लभ मृदा तत्त्व आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स व सौर ऊर्जा कार्यों में अत्यंत उपयोगी तत्त्व हैं। इन धातुओं का उपयोग सेलफोन से लेकर पवन चक्कियों तक में होता है। समस्या है कि इनके भंडार कुछ ही देशों में सिमटे हुए हैं। चीन इनमें से एक प्रमुख देश हैं। दुर्लभ मृदाओं के महत्त्व को देखते हुए चीन ने फैसला किया है कि वह इनके निष्कर्षण व उत्पादन पर सख्ती से नियंत्रण करेगा। उसने इनके निर्यात में कोटा सिस्टम लागू की है। इसके पीछे मकसद संभवतः अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का है।

यूएस, युरोप और जापान ने विश्व व्यापार संगठन में औपचारिक रूप से शिकायक दर्ज की है कि चीन इन धातुओं के मुक्त व्यापार को रोक रहा है।

चीन इन 17 धातुओं के वैश्विक उत्पादन में 95 प्रतिशत का हिस्सेदार है। वैसे तो इन धातुओं को दुर्लभ मृदा कहते हैं मगर ये इतनी दुर्लभ भी नहीं हैं। इनका खनन लगभग किसी भी महाद्वीप पर किया जा सकता है। दिक्कत यह है कि अन्य जगहों पर इनका निष्कर्षण महंगा पड़ता है। मगर चीन ने जो निर्यात कोटा सिस्टम लागू किया है उसके चलते इन धातुओं के भाव बढ़ गए हैं और अब अन्यत्र भी इनका उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो चला है।

वैसे अब कई कंपनियां चीन के बाहर दुर्लभ मृदा धातुओं का निष्कर्षण व उत्पादन करने लगी हैं। कई लोग मानते हैं कि निष्कर्षण व उत्पादन को चीन से बाहर करने के कई अन्य फायदे भी हैं। जैसे दुर्लभ मृदा धातुओं के साथ अक्सर रेडियोधर्मी युरेनियम और थोरियम भी पाए जाते हैं। इन्हें सावधानीपूर्वक अलग करके ठिकाने लगाना होता है। इस प्रक्रिया में विषैले तेज़ाबों का उपयोग होता है। लिहाज़ा यह अच्छा ही होगा यदि खनन उन देशों में हो जहां नियमन की सख्त व्यवस्था है। आजकल चीन स्वयं भी सख्त नियमन लागू कर रहा है। सिर्फ उन्हीं कंपनियों को निर्यात की अनुमति दी जाती है जो इन नियम-कायदों का पालन करें। यह सही दिशा में कदम माना जा रहा है। ***(स्रोत फीचर्स)***